रणजीत टाइम्स

वर्ष : 1, अंक: 106 इंदौर, शुक्रवार 18 अप्रैल 2025

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

DIGITAL EDITION

मेरे जन्मदिवस पर पोस्टर-बैनर नहीं लगाएं

गौसेवा करें मंत्री विजयवर्गीय

रंजीत टाइम्स» » आदित्य शर्मा

भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से विशेष अपील की है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर आग्रह किया है कि आगामी 30 अप्रैल को उनके जन्मदिवस पर शहर में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं लगाए जाएं।

विजयवर्गीय ने अपने संदेश में कहा, "आप सभी मेरे हृदय में बसते हैं। दीवारों पर तस्वीरें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।" उन्होंने कहा कि जो राशि पोस्टर और बैनर पर खर्च कर रहे हैं, उसे गौसेवा में लगाना अधिक पुण्य का कार्य होगा। उन्होंने इंदौर स्थित पितृ पर्वत गौशाला, श्रीश्री विद्याधाम गौशाला एवं साईं बाबा मंदिर के समीप स्थित गौशाला सहित शहर की अन्य गौशालाओं में दान करने का अनुरोध किया। अपने संदेश में मंत्री विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि शहर की स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है और अनावश्यक पोस्टर-बैनर लगाने से शहर का सौंदर्य बिगड़ता है। शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि ऐसे प्रचार के माध्यमों से बचा जाए।

गौरतलब है कि

मंत्री विजयवर्गीय का तिथि अनुसार जन्मदिवस 30 अप्रैल 2025 को है और इसे लेकर इंदौर सहित अन्य स्थानों पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसी क्रम में कई स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे थे, जिसे देखते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने यह भावनात्मक अपील की है। उनकी यह पहल न केवल सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण है, बल्कि पर्यावरण और गौसेवा के प्रति भी उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया गया कॉंग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर किया ज़ोरदार प्रदर्शन

रंजीत टाइम्स » अनिल चौधरी

इंदौर। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राजवाड़ा पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदर्शन के बाद पुतला दहन किया गया। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष श्री सौगात मिश्रा ने कहा कि ईडी देश की सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है जो कि बड़े घोटाले को उजागर कर रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर घोटाले के आप उनकी ही सरकार के समय दर्ज किए गए थे अब जब ईडी सही दिशा में जांच कर रही है तब यह दोनों और उनकी पार्टी ईडी कार्यालय जाकर अधिकारियों को धमकाने और जांच को भटकाने का कार्य कर रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने देश को लूटने का कार्य किया है।

इस अवसर पर नाना चौधरी, अजय अग्निहोत्री आवेश राठौर, अंकुर पाण्डेय, नवदीप चुटेले, आकाश नायक,रजत शर्मा, संतोष रघुवंशी, राहुल अवस्थी रोनक उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नरवाई जलाने पर आज 10 किसानों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज, अब तक 13 एफआईआर दर्ज

रंजीत टाइम्स

इंदौर जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 10 किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब तक कुल 13 किसानों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। अभियान चलाकर की जा रही इस कार्रवाई में नरवाई जलाने वालों से अर्थ दंड भी वसूला जा रहा है।

यह कार्यवाही आगामी दिनों में भी निरन्तर जारी रहेगी। जिले में आज कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर कनाडिया क्षेत्र में एक, मल्हारगंज में एक, खुड़ैल में एक, राऊ में 3, डॉ, अम्बेडकर नगर महू में एक, सांवेर में दो तथा देपालपुर में एक, इस तरह कुल 10 एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज करायी जा चुकी है।

जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि से संबंधित मैदानी अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा पंचायत सचिवों के साथ समन्वय कर कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों से किसानों को अवगत कराया जा रहा है।

किसानों से अपील की जा रही है कि नरवाई न जलाएँ, नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। किसान यदि नरवाई जलाता है तो राज्य शासन के नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड का प्रावधान निर्धारित किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। जिसके पास 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 5 हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा तथा जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।

महापौर द्वारा वार्ड क्रमांक 48 के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण

रंजीत टाइम्स

इंदौर । महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव द्वारा आज वार्ड क्रमांक 48 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती विजयलक्ष्मी गोहर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। महापौर श्री भार्गव ने सर्वप्रथम गीता भवन चौराहा से सेंट पॉल स्कूल तक की सड़क एवं ट्रैफिक व्यवस्था का जायज़ा लिया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों द्वारा ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं की जानकारी दी गई, जिस पर महापौर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इसके पश्चात महापौर द्वारा बड़ी गवालटोली रोड का निरीक्षण किया गया, जहाँ स्टॉर्म वाटर लाइन की व्यवस्था की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि बारिश के पहले सभी नालियों और स्टॉर्म वाटर लाइनों की सफाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के क्रम में महापौर जी द्वारा सेवा सरदार नगर स्थित योगा शेड पहुँचे, जहाँ उन्होंने योगाभ्यास हेतु नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली एवं आवश्यक सुधार हेतु दिशा-निर्देश दिए। अंत में महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने सेंट पॉल स्कूल चौराहा पर प्रस्तावित चौड़ीकरण कार्य की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नगर निगम नागरिकों की सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है और सभी क्षेत्रों में विकास कार्य समयबद्ध रूप से किए जाएंगे।

सीआरपीएफ है तो मुझे जीत का पूरा भरोसा है

एमपी के नीमच में बोले अमित शाह, परेड की ली सलामी

भोपाल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्यप्रदेश के नीमच में कहा, कहीं अशांति होती है और मुझे पता लगता है कि सीआरपीएफ तैनात है तो जीत का भरोसा रहता है। शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया हो जाएगा। इसमें सीआरपीएफ जवानों की भी बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने ये बातें

- **कहा-पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश होगा नक्सलवाद से मुक्त**

सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में कही। इससे पहले शाह ने शहीद स्थल पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। गृहमंत्री ने परेड की सलामी ली। शाह ने वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ जवानों को वीरता पदक भी दिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ की स्थापना से अब

तक 2264 जवानों ने अलग-अलग मोर्चों पर देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। उन सभी शहीदों के परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि 2047 में सर्वोच्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें आपके परिवारजन के बलिदान का बड़ा योगदान है। सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी देश में कहीं भी अशांति होती है। गृहमंत्री होने के नाते मुझे पता चलता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद हैं तो मैं निश्चित होकर काम करता हूं। मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सुनिश्चित है।

सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में वर्ष 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। इस प्रण को पूरा करने में सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सीआरपीएफ ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जरूरत होती है, सीआरपीएफ के जवान सदैव कर्तव्य पथ पर तत्पर रहते हैं। देश का जब भी स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, उसमें सीआरपीएफ के शहीदों के नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिह, क्षेत्र के लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर सहित जिले के तीनों विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ के कर्मियों के अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की।

गुरुग्राम लैंड स्कैम, वाड्रा से तीसरे दिन भी पूछताछ

- **राजनीतिक रूप से बदला ले रहे**

चंडीगढ़ (एजेंसी)। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय की गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। वह सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। एजेंसी अब तक वाड्रा से 2 दिनों में 8 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इसे लेकर गुरुवार को वाड्रा ने कहा- यह राजनीतिक

प्रतिशोध है। एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह गलत है। एजेंसियां देश में पद के किसी उम्मीदवार के पीछे पड़ जाती हैं या जब कोई पार्टी अच्छा काम कर रही होती है, तो उसे पकड़ लेती हैं। एजेंसियों पर भरोसा कैसे होगा। ईडी ने भाजपा के किस मंत्री या सदस्य को समन भेजा है। क्या भाजपा में सभी अच्छे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं। वाड्रा बोले कि भाजपा नेताओं पर भी कई आरोप हैं। उन्होंने कहा- मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अगर मुझ पर दबाव डालेंगे या परेशान करेंगे तो मैं और मजबूत होकर उभरूंगा।

चीन से बोरिया-बिस्तर समेट रहीं अमेरिका की कंपनियां

फायदा उठाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान तैयार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देशों अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिका ने चीनी माल पर 245 फीसदी टैक्स लगा दिया है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में सामान बनाना फायदे का सौदा नहीं रह गया है और वे चीन में अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में हैं। भारत सरकार इसे एक बड़े मौके के रूप में देख रही है। सरकार चाहती है कि ये कंपनियां भारत में आकर अपना कारोबार करें। इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और दवाइयों जैसे सेक्टरों में फायदा होगा। एक खबर के मुताबिक सरकार भारतीय कंपनियों को भी अमरीका में कारोबार बढ़ाने में मदद करना चाहती है। हाल ही में सरकार ने इंडस्ट्री के लोगों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में अमरीका में कारोबार बढ़ाने के तरीकों पर बात हुई। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। इस बारे में बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है। पहले वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होगी और फिर मई के मध्य से आमने-सामने मीटिंग होने की संभावना है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को इसमें एक बड़ा मौका दिख रहा है। अमरीका ने चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया है। लेकिन भारत और 75 से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पर टैक्स नहीं लगाया है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर नया टैक्स लगाएंगे।

एमपी के 9 शहरों में पारा 40 डिग्री पार

तेज धूप से बचने भोपाल में छाते निकले

भोपाल। मध्यप्रदेश में ओले-बारिश और आंधी का सिस्टम कमजोर पड़ते ही गर्मी का असर बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में धूप से बचने के लिए छाते निकल गए हैं। इंदौर में टेंट के नीचे बारातें निकल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, मालवा-निमाड़ यानी, इंदौर-उज्जैन संभाग सबसे गर्म है। ग्वालियर, चंबल संभाग में भी गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा

- **इंदौर में टेंट के नीचे से निकल रहीं बारातें**

दी हैं। दोपहर में लोग बेहद जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं, इसलिए सड़कें लगभग सूनी हो गईं। बुधवार को प्रदेश के 9 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इनमें रतलाम, नर्मदापुरम, खंडवा, शाजापुर, खरगोन, नरसिंहपुर, उज्जैन, धार और गुना शामिल हैं।

सबसे गर्म रतलाम रहा। जहां तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में 41.6 डिग्री, खंडवा में 41.5 डिग्री, शाजापुर में 41.1 डिग्री और खंडवा-नरसिंहपुर में पारा 41 डिग्री रहा। उज्जैन में 40.7 डिग्री, धार में 40.4 डिग्री और गुना में पारा 40.3 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्से में गर्मी का असर रहने की संभावना जताई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी पारे में बढ़ोतरी हो सकती है।

प्रदेश में बुधवार को गर्मी के साथ बारिश का दौर भी रहा। धार के मनावर में शाम को आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। वहीं, पांढुर्णा में भी पानी गिरा। रात में खरगोन, बालाघाट, सिवनी, मंडला, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में भी मौसम बदला रहा। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रैकवार ने बताया, 18 अप्रैल तक तेज गर्मी की संभावना है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है।

नई नियुक्ति पर रोक संपत्तियां पहले जैसी ही रहेंगी

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया फिलहाल कोई स्टे

नई दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 7 दिन का

- **केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए दिया एक हफ्ते का वक्त**

वक्त दिया। वहीं शीर्ष कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस कानून को लेकर पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले जैसी बनी रहेगी। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। चीफ

जस्टिस ने कहा कि अगली सुनवाई तक बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती, और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका निर्णय लेती है और न्यायपालिका निर्णय लेती है। सीजेआई ने कुछ खास लोगों को 2013 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने की इजाजत दी है। यह एक विशेष मामला है। सीजेआई ने कहा, याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने की अनुमति है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। सभी को जल्द से जल्द जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ता सिर्फ 5 याचिकाएं ही दें। सुनवाई में कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि वह तीन मुद्दों पर अंतरिम आदेश जारी करेगा। इसका मतलब है कि कोर्ट अभी कुछ समय के लिए ये नियम लागू करेगा। पहला मुद्दा वक्फ संपत्तियों से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा, जिन संपत्तियों को कोर्ट ने वक्फ घोषित कर दिया है, उन्हें वक्फ से हटाया नहीं जाएगा। चाहे वो वक्फ इस्तेमाल से बनी हो या घोषणा से, उन्हें वक्फ ही माना जाएगा। दूसरा मुद्दा कलेक्टर की कार्यवाही से जुड़ा है। कलेक्टर अपनी कार्यवाही जारी रख सकते हैं। लेकिन, कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे।

एएपी नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर गुरुवार को सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर हो रही है। सीबीआई ने बुधवार को एएपी के खिलाफ फॉरेन

कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक- विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 बार में पार्टी को कुल1.02 करोड़ का डोनेशन दिया। कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया, जिससे फर्जीवाड़े का संदेह है। एएपी ने जवाब में कहा-पार्टी को विदेशियों ने डोनेशन दिया।

प्रमोशन की तैयारियों के बीच मांगी रिक्त पदों की जानकारी

- **विभाग प्रमुखों ने संभागीय अधिकारियों से मांगा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का ब्यौरा**

भोपाल। मोहन यादव सरकार ने नौ साल से पेंडिंग कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन के लिए रास्ता निकालने के बाद पदोन्नति के कारण रिक्त होने वाले पदों और पहले से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते उच्च शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग समेत कई विभागों ने संभागीय अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मांगी है। यह जानकारी अप्रैल माह में ही देने के लिए कहा गया है। इसी के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से एक हफ्ते में ही कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है ताकि आने

वाले समय में इसकी समीक्षा कर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सके। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों के तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में यह जानकारी क्षेत्री अतिरिक्त संचालकों के माध्यम से मांगी है। उच्च शिक्षा आयुक्त ने इसको लेकर सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी शासकीय कालेज में रिक्त पदों की संभागवार पूरी जानकारी मंगाकर शासन को भेजें। इसमें कालेजों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत, नियमित, आकस्मिक निधि और आउटसोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी शामिल है। विभाग ने तृतीय श्रेणी कैडर के जिन पदों की जानकारी मांगी है उसमें हॉस्टल मैनेजर, मुख्य लिपिक, मुख्य लिपिक कम लेखापाल और इससे नीचे के पद के कर्मचारी शामिल हैं।

रणजीत टाइम्स
इंदौर, शुक्रवार 18 अप्रैल 2025
03
DIGITAL EDITION

‘बंगाल में हिंसा प्रायोजित और सरकार प्रायोजक’, कैलाश विजयवर्गीय का ममता पर सीधा वार

कहा - मुख्यमंत्री खुद हिंसा करवा रहीं, राज्य को बना दिया असुरक्षा और अराजकता का अड्डा

मंदसौर। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, वह कोई सामान्य जन आक्रोश नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और प्रायोजित हिंसा है, जिसे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरपरस्ती में अंजाम दिया जा रहा है। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ऐसा माहौल जानबूझकर बनवा रही हैं क्योंकि वहां हिंदुओं की आबादी तीस प्रतिशत है और वह उन्हें डराने का काम कर रही हैं। मंत्री ने याद दिलाया कि कुछ साल पहले जब वे खुद उसी इलाके में पहुंचे थे, तब उन्हें भी भीड़ ने घेर लिया था और जान का खतरा उत्पन्न हो गया था। उन्होंने बताया कि यह इलाका पश्चिम बंगाल से महज 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसी मार्ग से राज्य सरकार की मिलीभगत से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नक्सलियों तक हथियारों की आपूर्ति की जाती है। विजयवर्गीय का कहना था कि ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल को पूरी तरह से अराजकता की ओर धकेल दिया है, जहां कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि अब जनता को यह अच्छी तरह समझ आ गया है कि ममता को वोट देने का मतलब क्या है– बेरोजगारी, कारखानों की बंदी, महिलाओं की असुरक्षा और लगातार बढ़ती हिंसा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में ममता सरकार का पूरी तरह सफाया हो जाएगा और बंगाल एक नए युग की ओर बढ़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर के कालाखेत मैदान में चल रहे महा सोम यज्ञ में भाग लेने के लिए गुरुवार को पहुंचे थे। यज्ञ में भाग लेकर उन्होंने हवन कुंड की परिक्रमा की और वैदिक विधि अनुसार आहुति दी। धार्मिक अनुष्ठान के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए न केवल बंगाल की स्थिति पर चिंता जताई बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों का भी मजबूती से समर्थन किया।नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूरा मामला कोर्ट की निगरानी में चल रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2021 में कोर्ट ने ही ईडी को जांच के निर्देश दिए थे और उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार पर आरोप लगाना बेबुनियाद है।

वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि जब एक राज्य की सरकार खुद अराजक तत्वों को संरक्षण देने लगे, तब वहां लोकतंत्र और कानून व्यवस्था की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। मुर्शिदाबाद में 10 अप्रैल से लगातार हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया, सड़कों पर जाम लगा दिया और रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। स्थिति को काबू में लाने के लिए केंद्र सरकार ने बीएसएफ की करीब 300 जवानों की तैनाती पहले ही कर रखी थी, लेकिन हालात बिगड़ने पर पांच अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा कंपनियों को भी भेजा गया है।

शादी का झांसा, लुटी आबरू और ऐंठ लिए तीन लाख: जब बेवफाई की भनक लगी तो थाने पहुंची प्रेमिका, अब आरोपी पर केस दर्ज

रीवा। प्यार के नाम पर धोखा, दरिंदगी और फिर आर्थिक शोषण की एक दर्दनाक कहानी रीवा जिले से सामने आई है, जहां एक युवती को पहले शादी का सपना दिखाया गया, फिर उसकी आबरू से खिलवाड़ किया गया और अंत में उससे तीन लाख रुपये ऐंठ लिए गए। यह मामला सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़िता का दर्द उस समय और गहरा हो गया जब उसे पता चला कि जिससे वह तीन साल से प्रेम कर रही थी और शादी की उम्मीद लगाए बैठी थी, वह अब किसी और लड़की से विवाह करने जा रहा है। घटना रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी मुलाकात सतना जिले के बिरौली गांव निवासी शुभम बुनकर से तीन साल पहले मोबाइल फोन के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और फिर शुभम ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाना शुरू किया। इस दौरान आरोपी ने उसे कई बार यह कहकर भावनात्मक रूप से प्रभावित किया कि वह विभिन्न पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। युवती ने प्रेम और भरोसे के चलते धीरे-धीरे उसे तीन लाख रुपये दे दिए, इस उम्मीद में कि वह उसका जीवनसाथी बनेगा।

लेकिन जब युवती को यह जानकारी मिली कि शुभम दो दिन बाद किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है, तो उसका दिल टूट गया। इस विश्वासघात के बाद उसने हिम्मत जुटाकर थाने का रुख किया और पूरी कहानी पुलिस के सामने रखी। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक शुभम बुनकर के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आर्थिक शोषण के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि पीड़िता के विस्तृत बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह घटना सिर्फ एक युवती के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो प्यार और रिश्तों को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीड़िता की मानसिक और आर्थिक पीड़ा ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक महिलाएं इस तरह के झूठे वादों का शिकार बनती रहेंगी।

ग्वालियर-चंबल अंचल के 300 से अधिक सरकारी स्कूलों में आज भी नहीं है बिजली, 21 साल से इंतजार कर रहे छात्र, गर्मी में बेहाल मासूमों की सुनने वाला कोई नहीं

ग्वालियर। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूलों की हालत आज भी बदतर बनी हुई है, लेकिन जब उन स्कूलों में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा भी न हो, तो यह स्थिति और भी शर्मनाक हो जाती है। ग्वालियर-चंबल अंचल में सामने आई यह तस्वीर किसी एक-दो स्कूलों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के शैक्षणिक ढांचे पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मई की शुरुआत में ही जब तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, ऐसे में अंचल के 300 से अधिक सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां बिजली कनेक्शन तक नहीं है। अकेले ग्वालियर जिले की बात करें तो 89 सरकारी स्कूलों में आज तक बिजली की लाइन तक नहीं पहुंची है। ये वे स्कूल हैं जहां कई बार छात्र 12 से 21 साल तक गर्मी और असुविधा से जूझते हुए पढ़ते रहे, लेकिन कोई भी सरकारी योजना उनकी ज़िंदगी में रौशनी नहीं ला पाई।

ग्वालियर जिले के गोल पहाड़िया इलाके के आदिवासी पुरा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की कहानी इस बदहाली की गवाही खुद देती है। इस स्कूल की बिल्डिंग करीब 21 साल पहले तैयार की गई थी, लेकिन आज तक वहां बिजली का कनेक्शन नहीं हो सका है। यहां कुल 53 छात्र-छात्राएं पढ़ाई के लिए आते हैं, जो एक हाथ में पेंसिल थामे अपने भविष्य की इबारत लिखने की कोशिश करते हैं और दूसरे हाथ से किताबों या नोटबुक से खुद को हवा करते हैं ताकि गर्म हवा की मार को थोड़ा कम कर सकें। इन मासूम बच्चों का यह संघर्ष केवल शिक्षा के लिए है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही उनके हौसले को चुनौती देती है। गर्मी के कारण यहां बच्चों की उपस्थिति लगातार घट रही है, क्योंकि बिना बिजली के न पंखे चलते हैं और न ही पीने का पानी समय पर उपलब्ध हो पाता है। पीने का पानी भी दूर से मंगवाया जाता है और वह खत्म होने पर कई बार छात्रों को बिना पानी के ही गुजारा करना पड़ता है। बघेलों का पूरा स्थित शासकीय शरणार्थी गोरखी मिडिल स्कूल की तस्वीर भी इससे अलग नहीं है। यहां कुल 54 छात्र-छात्राओं के नाम दर्ज हैं लेकिन जब टीम पहुंची तो

मात्र 7 छात्र ही स्कूल में मौजूद मिले। बाकी बच्चों ने भीषण गर्मी, बिजली की अनुपस्थिति और पानी की किल्लत के चलते स्कूल आना छोड़ दिया है। यह स्कूल पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है जहां सामान्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में तापमान 2 से 3 डिग्री अधिक रहता है। स्कूल भवन साफ-सुथरा है, अच्छी बेंचें हैं, लेकिन जब बिजली नहीं है, तो वे सब बेकार हैं। यहां पिछले 12 वर्षों से बिजली कनेक्शन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। शिक्षिकाएं भी यह स्वीकार करती हैं कि इतनी गर्मी में बच्चों को पढ़ाना कठिन होता है, और खुद उन्हें भी असुविधा होती है।

इस गंभीर मुद्दे पर जब स्कूल शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर दीपक पांडे से सवाल किया गया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि ग्वालियर जिले के 89 स्कूलों सहित पूरे अंचल में कई स्कूल ऐसे हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। उनकी मानें तो अधिकांश स्थानों पर या तो स्कूल ट्रांसफार्मर से काफी दूर हैं या फिर बिजली के पोल ही नहीं लगाए गए हैं। इस समस्या की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और जैसे ही फंड प्राप्त होगा, प्राथमिकता के आधार पर इन स्कूलों में बिजली कनेक्शन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या 21 साल का इंतजार काफी नहीं था? जब देश के भविष्य कहे जाने वाले मासूम बच्चे बिना बिजली और बिना पानी के इस भीषण गर्मी में शिक्षा हासिल करने का प्रयास करते हैं, तब यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की नहीं, बल्कि पूरे शासन-प्रशासन की असफलता का प्रमाण बन जाता है। आज ये छात्र इस उम्मीद में स्कूल आ रहे हैं कि कभी तो उनके स्कूलों में भी पंखे चलेंगे, कभी तो कक्षाएं ठंडी रहेंगी, कभी तो पानी समय पर मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि अब जब यह मामला सार्वजनिक हुआ है, तो संबंधित अधिकारी और प्रशासन हरकत में आएंगे और ग्वालियर-चंबल अंचल के इन अंधेरे में डूबे स्कूलों को बिजली की रौशनी से रोशन करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।

16.71 लाख का जुर्माना, विरोध में उतरे किसान संगठन

इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने खेतों में नरवाई यानी पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने बीते कुछ दिनों में व्यापक कार्रवाई करते हुए 770 किसानों पर कुल 16.71 लाख रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है। यही नहीं, नियमों के उल्लंघन पर खेत मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद जिलेभर में किसानों में हलचल है और कृषक संगठनों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रशासन के रवैये का विरोध शुरू कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि इंदौर जैसे शहर में पराली जलाने की घटनाएं केवल ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित समस्या नहीं हैं, बल्कि इसका सीधा असर शहरी क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ

शहर है और इसकी पहचान को बनाए रखना सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश का उद्देश्य खेतों में नरवाई जलाने से पर्यावरण, आमजन और जीव-जंतुओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकना है। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिले में बीते चार दिनों के भीतर खेतों में नरवाई जलाने की 770 घटनाएं सामने आई हैं, जिनके आधार पर संबंधित किसानों पर कुल 16 लाख 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं, आदेश के उल्लंघन पर अब तक तीन किसानों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। इन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दोषी को एक वर्ष तक के कारावास, पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है। हालांकि प्रशासन की इस सख्ती के खिलाफ अब कृषक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पश्चिमी मध्यप्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में सक्रिय संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक रामस्वरूप मंत्री ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि खेतों में पराली जलाना पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इसके समाधान के लिए किसानों को पहले विकल्प और जागरूकता उपलब्ध कराना चाहिए था। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कृषि विभाग के अफसरों को गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करना चाहिए और पराली नष्ट करने के वैकल्पिक तरीकों की जानकारी देना चाहिए। रामस्वरूप मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि वह किसानों को मशीनरी और संसाधनों के लिए अनुदान दे, ताकि किसान मजबूरी में पराली जलाने जैसा कदम न उठाएं।

गौरतलब है कि खेतों में पराली जलाने व घटनाएं हर साल खासतौर से रबी और खरी फसलों की कटाई के बाद बढ़ जाती हैं। इ प्रक्रिया में निकलने वाला धुआं वायु प्रदूष का बड़ा कारण बनता है, जिससे सांस संबं बीमारियों में भी इजाफा होता है। सुप्रीम को और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले ही इस प कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। इसके बावजूद इ घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाता। इंदे प्रशासन की यह ताज़ा कार्रवाई एक मिसा बन सकती है, बशर्ते इसमें संवेदनशील और समन्वय का संतुलन बना रहे। इस पू स्थिति में एक तरफ प्रशासन पर्यावरण सुर के लिए सख्ती बरत रहा है, तो दूसरी अ किसान संगठन इसे एकतरफा और कठ कदम बताते हुए विरोध जता रहे हैं। अ देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह टकरा किस दिशा में जाता है और क्या प्रशास किसानों के हितों और पर्यावरण सुरक्षा के बी संतुलन बनाने में सफल हो पाता है या नहीं।

ईमेल से मिली धमकी से थर्राया इंदौर: पंजाब नेशनल बैंक को बम से उड़ाने की चेतावनी के बाद मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां

इंदौर। आर्थिक राजधानी में हड़कंप मच गया, जब पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गुरुवार सुबह सियागंज स्थित सीबीबी ब्रांच के ईमेल पर एक अज्ञात मेल प्राप्त हुआ, जिसमें बैंक को विस्फोट से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। ईमेल मिलते ही बैंक अधिकारियों ने घबराते हुए तुरंत इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इस अलर्ट के बाद पुलिस महकमा और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गईं। देखते ही देखते बैंक परिसर और उसके आसपास का इलाका पुलिस की घेराबंदी में आ गया।

पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बम डिस्पोजल स्क्वॉड (ब्रष्ठस्) को मौके पर बुलाया। टीम के साथ कोतवाली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और बैंक परिसर की बारीकी से तलाशी ली गई। जांच अभियान में बैंक के हर कोने और आसपास के इलाके को खंगाला गया, लेकिन घंटों चली पड़ताल के बावजूद कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। तलाशी के दौरान बैंक स्टाफ और आम नागरिकों में भय और बेचैनी का माहौल बना रहा। लोग किसी अनहोनी की आशंका से परेशान थे, लेकिन जब पुलिस ने बैंक को पूरी तरह से क्लियर घोषित किया, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली।

फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया है और ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। प्रारंभिक जांच में यह मेल फर्जी प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस इस संभावना को भी खारिज नहीं कर रही कि यह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है या फिर जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। सायबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें इस ईमेल की ट्रेसिंग में लगी हैं और हर तकनीकी पहलू की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कहीं यह किसी पुराने आपराधिक तत्व की हरकत तो नहीं। इस घटना ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह तकनीक का इस्तेमाल अब शरारती तत्वों और अपराधियों के हाथ में एक खतरनाक हथियार बनता जा रहा है। किसी एक मेल से पूरा सिस्टम झकझोर दिया गया और संसाधनों को घंटों तक एक काल्पनिक खतरे से निपटने में झोंकना पड़ा। हालांकि, प्रशासन का त्वरित एक्शन सराहनीय रहा जिसने समय रहते हालात को संभाल लिया। अब सबकी नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर है। क्या जल्द ही मेल भेजने वाले की पहचान हो पाएगी? क्या उसके पीछे कोई संगठित प्रयास है या फिर यह केवल किसी की शरारत? यह आने वाली जांच में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस घटना ने इंदौर जैसे शांत और व्यवस्थित शहर में अस्थायी रूप से दहशत जरूर फैला दी है।

एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला अत्याधुनिक बस टर्मिनल, संचालन के लिए प्राधिकरण देगा 20 साल का ठेका

इंदौर। यातायात व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा एमआर 10 स्थित कुमेर्डी में लगभग 110 करोड़ रुपये की लागत से एक ऐसा आईएसबीटी (इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल) तैयार किया गया है, जो पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है और जिसमें यात्रियों को हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह बस टर्मिनल न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श मॉडल बनने जा रहा है। अब इस बस टर्मिनल के संचालन और रखरखाव के लिए 20 वर्षों के लिए निजी एजेंसी को ठेका देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। बीते दिनों आमंत्रित किए गए टेंडरों को लेकर काफी दिलचस्पी देखी गई और आज शाम को प्राधिकरण के दफ्तर में इन टेंडरों को खोला जाएगा। प्राधिकरण द्वारा निर्मित यह आईएसबीटी 15 एकड़ के विशाल भूखंड पर विकसित किया गया है, जिसमें यात्रियों की हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। इस टर्मिनल से करीब 1400 से अधिक बसों का संचालन होगा, जो कि वातानुकूलित और हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त होगा। यहां 43 बस प्लेटफार्म बनाए गए हैं, ताकि विभिन्न शहरों के लिए जाने वाली बसों का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो सके। गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर जैसे प्रमुख शहरों के लिए यहां से बसें चलेंगी, जिससे यात्रीगण एक ही स्थान से पूरे क्षेत्र में सफर कर सकेंगे। इस टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा के लिए 14 टिकट काउंटर बनाए गए हैं और साथ ही एक हजार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।

प्राधिकरण का उद्देश्य सिर्फ एक नया बस स्टैंड बना नहीं बल्कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट हब तैयार करना है जो यात्रि के लिए पूरी तरह आरामदायक, सुरक्षित और हाईटेक हो। य कारण है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इस बस टर्मिन का निरीक्षण करते हुए इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। य टर्मिनल मेट्रो स्टेशन से भी सीधे जोड़ा जा रहा है, जिस यात्रियों को पैदल पुल के जरिए बस और मेट्रो के बीच सी और सहज संपर्क मिल सकेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार ने जानकारी दी कि कुमेर्डी में निर्मि इस अत्याधुनिक आईएसबीटी के संचालन के लिए बीते दि टेंडर आमंत्रित किए गए थे और कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने इस रुचि दिखाई है। आज शाम को यह टेंडर खोले जाएंगे अ चयनित एजेंसी को 20 वर्षों के लिए संचालन का जिम सौंपा जाएगा। उनका कहना है कि हमारा प्रयास है कि ए सक्षम और योग्य एजेंसी का चयन किया जाए, जो इ टर्मिनल को न केवल अच्छी तरह संचालित कर सके, बलि इसकी गुणवत्ता और सुविधाओं को भी बनाए रखे। यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा एक अन्य बस टर्मिन नायता मुंडला क्षेत्र में भी आरटीओ भवन के पास बनवा गया था, जिसका संचालन कुछ समय पूर्व एआईसीटीएसए को सौंपा गया था, लेकिन वहां व्यवस्थाएं सुचारू नहीं च सकीं और फिलहाल वह टर्मिनल बंद पड़ा है। इसी अनुभ को देखते हुए अब कुमेर्डी के बस टर्मिनल को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही और शुरुआत से ही एक मजब और व्यवस्थित संचालन तंत्र की तलाश की जा रही है।

बीआरटीएस कॉरिडोर के मटेरियल से निगम को होगी लगभग पौने चार करोड़ की आय, जल्दी जारी होगा बीआरटीएस तोड़ने का टेंडर

निगम द्वारा कराए गए सर्वे में किया गया अनुमानित आय का आकलन

इंदौर। इंदौर नगर निगम द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर कराए गए सर्वे के मुताबिक बीआरटीएस कॉरिडोर के मलबे से निगम को 3.37 करोड़ की कमाई होगी जबकि उसे हटाने पर 34 लाख रुपए खर्च होंगे।

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़ने का फैसला लेने के बाद हाईकोर्ट ने भी इसपर अपनी मुहर लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि नगर निगम द्वारा इस कॉरिडोर को तोड़ने का काम कब शुरू किया जाएगा। इस कॉरिडोर में दोनों तरफ आरसीसी के बीम 10475 मीटर की लंबाई में, 0.35 मीटर की चौड़ाई में तथा 0.30 मीटर की गहराई में लगे हैं।इस पूरे बीम का आकलन किया जाए तो यह 2199 घनमीटर है। इसे तोड़ने का खर्चा 786 रुपए प्रति घनमीटर आता है। इस हिसाब से इसपर 17.29 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार इस पूरे कॉरिडोर में 18 बस शेल्टर होम हैं। हर बस शेल्टर होम की लंबाई 58 मीटर है। इस तरह से इनकी कुल लंबाई 1044 घनमीटर हो जाती है। इन्हें तोड़ने पर भी 786 रुपए प्रति घनमीटर की दर से कुल 8.20 लाख रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा चारों ओर आरसीसी के छोटे निर्माण किए हुए हैं, जो 10,475 वर्गमीटर की लंबाई और 0.88 वर्गमीटर की ऊंचाई में है। यह कार्य कुल 32207 घनमीटर के क्षेत्र में है। इसके अलावा 52,000 वर्गमीटर के क्षेत्र में स्क्रब्स बने हुए हैं, जिनकी लंबाई 1.25 मीटर और चौड़ाई व ऊंचाई 0.61 मीटर है। इस तरह यह निर्माण 40,105 घनमीटर क्षेत्र का है, जबकि बस शेल्टर होम का निर्माण 31,266 वर्गमीटर का है। बस शेल्टर होम के पास में स्टील की रैलिंग लगी हुई है। बस स्टैंड के दोनों तरफ 10,475 वर्गमीटर के क्षेत्र में 17.52 मीटर की चौड़ाई और गहराई में यह रैलिंग लगी हुई है, जिनका कुल क्षेत्रफल 3.67 लाख वर्गमीटर होता है। इस पर 1 रुपए प्रति किलो की दर से निकलवाने का खर्च आएगा। इस तरह इस बीआरटीएस के पूरे कॉरिडोर को तोड़ने और सामान निकालने पर 34.70 लाख रुपए खर्च होंगे।

इस तरह से होगी कमाई

निगम द्वारा कराए गए आकलन के अनुसार इस कॉरिडोर में से कुल 1.53 लाख किलो स्टील निकलेगा। यह स्टील 30 रुपए प्रति किलो के भाव से 46 लाख रुपए में बिकेगा। इसके अलावा बीआरटीएस में से 10 हजार मीटर लंबाई की रैलिंग निकलेंगी। इसके अतिरिक्त 90 फीसदी ए श्रेणी का स्क्रैप मटेरियल निकलेगा, जो 45 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा सकेगा। इससे नगर निगम को 2.31 करोड़ रुपए की कमाई होगी। बस शेल्टर होम के एक्स्ट्रा आइटम से निगम को 90 लाख रुपए की कमाई होगी। इस तरह इस पूरे कॉरिडोर को तोड़ने से निगम को 3.71 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

दो महीने का वक्त लगेगा तोड़ने में

नगर निगम जनकार्य विभाग के प्रभारी महापौर परिषद के सदस्य राजेंद्र राठौर ने बताया कि निगम द्वारा कराए गए आकलन के अनुसार बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। अब निगम जल्दी ही इस कॉरिडोर को तोड़ने के टेंडर जारी कर रहा है। इस टेंडर में भाग लेने वाले ठेकेदार को यह ऑफर देना होगा कि वह इस कार्य को करने के एवज में नगर निगम को कितनी राशि देगा। जिस ठेकेदार द्वारा तोड़ा जाएगा उसी ठेकेदार को सारा मलबा और मटेरियल भी मिल जाएगा। उसे निगम को यहां बताना होगा कि वह तोड़ने का खुद का खर्चा निकालने के बाद नगर निगम को कितना पैसा देगा। निगम द्वारा कराए गए आकलन के अनुसार निगम को कम से कम 3.37 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इससे ज्यादा राशि जो ठेकेदार देगा उससे अधिकतम राशि का आफर देने वाले को निगम द्वारा ठेका दिया जाएगा।

तेजस्वी-राहुल मुलाकात में भी नहीं बनी बात महागठबंधन में पेंच अभी फंसा है!

कांग्रेस के आक्रामक तेवरों को देखते हुए लालू यादव काफी हद तक असहज हो गए। उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव (जिन्हें वे पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं) को पटना में 17 अप्रैल को होने वाली महागठबंधन की बैठक से पहले ही राहुल गांधी के साथ सब कुछ तय करने के लिए आनन-फानन में दिल्ली भेजा। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर राहुल गांधी के साथ बैठक की। लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कांग्रेस की अहमियत बताने के लिए इसको एक बड़ी बैठक बना दिया। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और गुरदीप सिंह सप्पल भी मौजूद रहे। वहीं तेजस्वी यादव अपने साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव को लेकर गए थे।

संतोष कुमार पाठक

बिहार की राजनीति में 90 के दशक में लालू यादव के ताकतवर होने के साथ ही कांग्रेस समेत अन्य कई राजनीतिक दलों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे लालू यादव ने वर्ष 1990 में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा कर सबको चौंका दिया था। उस समय आडवाणी को जिस अधिकारी (आरके सिंह) ने गिरफ्तार किया था, उन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। वहीं सरकार को बनाए रखने के लिए लालू यादव ने अनगिनत बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को तो लालू यादव ने बिहार में अपनी बी टीम बनाकर छोड़ दिया था। लालू यादव सीधे कांग्रेस आलाकमान से डील किया करते थे और बिहार कांग्रेस के नेताओं को हमेशा लालू यादव से डर कर रहना पड़ता था।

बिहार में कांग्रेस नेताओं की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई नेताओं ने यह शिकायत भी की कि आरजेडी के नेता कांग्रेस नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सम्मान हासिल करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी के मिशन बिहार से काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है।

बिहार के लगातार दौरे पर जाकर राहुल गांधी ने राज्य की राजनीति को समझने का प्रयास किया। अपने करीबी नेता कृष्णा अल्लावरु को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाकर भेजा। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद कन्हैया कुमार को %पलायन रोको, नौकरी दो% यात्रा का चेहरा बनकर बिहार की सड़कों पर उतरने का मौका दिया। आने वाले दिनों में लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद पप्पू यादव को भी बड़ी भूमिका देने की खबरें निकल कर सामने आ रही है।

कांग्रेस के आक्रामक तेवरों को देखते हुए लालू यादव काफी हद तक असहज हो गए। उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव (जिन्हें वे पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं) को पटना में 17 अप्रैल को होने वाली महागठबंधन की बैठक से पहले ही राहुल गांधी के साथ सब कुछ तय करने के लिए आनन-फानन में दिल्ली भेजा। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर राहुल गांधी के साथ बैठक की। लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कांग्रेस की अहमियत बताने के लिए इसको एक बड़ी बैठक बना दिया। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय संगठन महासचिव

केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और गुरदीप सिंह सप्पल भी मौजूद रहे। वहीं तेजस्वी यादव अपने साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव को लेकर गए थे।

लेकिन तेजस्वी यादव की यह दिल्ली यात्रा उनके लिए उतनी लाभदायक नहीं रही, जितनी वह उम्मीद कर रहे थे। कांग्रेस ने आरजेडी के ऑफर (यानी 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने) को सिरे से नकार दिया और पिछली बार की तरह 70 सीटों की मांग रख दी। इतना ही नहीं कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछली बार की तरह कांग्रेस कमजोर और हारने वाली सीटों को स्वीकार नहीं करेगी। सीट को लेकर विस्तार से चर्चा पटना की बैठक में होगी। वहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते खोलने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली की बैठक बेनतीजा रही, यह बैठक के बाद आए बयानों से भी साफ पता चलता है। बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली आए तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि, ÷पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे के लिए। यह हम लोगों की चीजें हैं। हम लोगों की बातचीत के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।÷

मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पत्रकारों ने यही सवाल बैठक से बाहर आए कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा। कृष्णा अल्लावरु ने भी साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि , अगर पहली मुलाकात में ही सब कुछ तय हो गया होता तो वे इसकी जानकारी जरूर देते। मतलब साफ है कि गठबंधन में अभी काफी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस इस बार झुकने को तैयार नहीं है।

बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने है। आरजेडी चाहती थी कि पहले कांग्रेस के साथ सारे मुद्दे तय कर लिए जाएं, फिर गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाए। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में खरगे के आवास पर हुई पहले दौर की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई।

आपको बता दें कि, 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के तहत आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई (एमएल) 19, सीपीआई 6 और सीपीआई (एम) 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन की बात करें तो, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई(एमएल) को 12 और सीपीआई एवं सीपीआई(एम) को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

आरजेडी कांग्रेस को 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीतने की याद दिलाते हुए, इस बार सिर्फ 50 सीटों पर लड़ने की बात कह रहा है। जबकि कांग्रेस 70 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सबकी निगाहें, 17 अप्रैल को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक पर टिक गई है। कांग्रेस सीटों की संख्या और सीटों के नाम के ऐलान के साथ ही उपमुख्यमंत्री के पद पर भी अड़ गई है। आरजेडी जब तक इन मुद्दों पर कांग्रेस की बात नहीं मान लेती है, तब तक कांग्रेस भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस इस बार एक साझा कार्यक्रम के आधार पर चुनाव में जाना चाहती है।

पुलिस ने ऑनलाईन IPL क्रिकेट सट्टा खेलने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार

खरगोन

वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत, अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन मे जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) व थाना प्रभारियों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी तारतम्य मे थाना मंडलेश्वर पर IPL क्रिकेट सट्टा खेलने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

बुधवार को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि, थाना मंडलेश्वर क्षेत्रानंतर्गत कुछ लोग आई.पी. एल. दिल्ली व राजस्थान के टी-20 क्रिकेट मैच में हार जीत का दाव लगाकर रूपये पैसो से सट्टा खेल रहे है । उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी मंडलेश्वर उनि दीपक यादव के नेतृत्व मे थाना मंडलेश्वर से पुलिस टीम का गठन किया गया मुखबिर के की सूचना से अवगत करवा कर सूचना की तस्दिक हेतु रवाना किया गया।

एनएसएल ने 13 और 14 अप्रैल 2025 को ऐतिहासिक उच्चतम उत्पादन दर्ज किया

नगरनार, (छत्तीसगढ़)। नगरनार स्टील लिमिटेड (एनएसएल) ने 13 तथा 14 अप्रैल, 2025 को प्रचालन ऐतिहासिक प्रचालन मील के पत्थर हासिल किए, सभी प्रमुख इकाइयों ने रिकॉर्ड-तोड़ उत्पादन किया - जो संयंत्र की प्रक्रिया उत्कृष्टता और भारत के इस्पात क्षेत्र में इसकी बढ़ती ताकत दोनों को उजागर करता है।

13 अप्रैल, 2025 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, एनएसएल के ब्लास्ट फर्नेस ने एक ही दिन में 10,169 टन हॉट मेटल का ऐतिहासिक उत्पादन हासिल किया, जो इसकी डिज़ाइन की गई अधिकतम क्षमता को पार कर गया और 2.26 टन/घन मीटर/दिन के उत्पादन तक पहुंच गया। अगस्त 2023 में चालू की गई इस फर्नेस की उपयोगी मात्रा 4,506 क्यूबिक मीटर है और इसे मूल रूप से 9,500 टीपीडी के औसत हॉट मेटल उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें 9,900 टीपीडी की रेटेड पीक तथा 2.2 टन/द्वश/दिन का डिज़ाइन था। प्रचालन के एक वर्ष से भी कम समय में ऐसा प्रदर्शन हासिल करना, एनएसएल की प्रक्रियाओं में अंतर्निहित तकनीकी उत्कृष्टता और प्रचालन प्रबंधन को उजागर करता है।

14 अप्रैल, 2025 को एनएसएल के एक और रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन में, सिंटर प्लांट ने 12,385 टन का अपना अब तक का सबसे अधिक दैनिक उत्पादन दर्ज किया, हॉट स्ट्रिप मिल ने 8,260 टन एचआर कॉइल उत्पादन के साथ एक नया बेंचमार्क हासिल किया तथा स्टील मेल्टिंग शॉप ने एक ही दिन में 47 हीट एवं 8,600 टन लिक्विड स्टील का प्रभावशाली उत्पादन हासिल किया, साथ ही कई अन्य उपलब्धियाँ भी हासिल कीं। ये परिणाम ऐसे समय में आए हैं जब एनएसएल पहले से ही अपने रेटेड प्रदर्शन स्तरों को पार कर रहा है, जो कमीशनिंग के बाद से इसकी बढ़ती गति का संकेत देता है।

एनएमडीसी स्टील के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री अमिताभ मुखर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि '' एनएसएल का ये ऐतिहासिक प्रदर्शन इस्पात निर्माता के रूप में हमारी यात्रा निर्णायक क्षण है। कमीशनिंग के कुछ महीनों के भीतर डिजाइन क्षमताओं को पार करना हमारी इंजीनियरिंग, प्रचालन तथा कुशल टीमों की असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करता है ये उपलब्धियां भारत के अग्रणी इस्पात निर्माताओं के बीच अपनी जगह बनाने के लिए एनएसएल की तत्परता का एक महत्वपूर्ण परिणाम हैं।

तनाएरा ने लॉन्च किया 'समर सॉन्ग्स', प्रकृति के स्वर और रंगों से प्रेरित हवादार कलेक्शन

खूबसूरत साड़ियों, कुर्तों, कुर्ता सेट, शिक टॉप एवं फ्लोई ड्रैसेज़ के साथ अपनी गर्मियों की वार्डरोब को दें नया लुक

मुंबई, एजेंसी। दिन लम्बे हो रहे हैं और हवाओं में गर्मी बढ़ती जा रही है, इस बीच तनाएरा लेकर आए हैं 'समर सॉन्स' एक कलेक्शन जो सूरज की रोशनी से जगमाते दिनों, हल्की हवाओं और प्रकृति के भव्य स्वर का सार है। इस कलेक्शन को उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भव्यता के साथ-साथ आराम का अनुभव भी पाना चाहती हैं। यह कलेक्शन हवादार कॉटन, मुलायम सिल्क, सिल्क कॉटन एवं हवादार ऑर्गेन्ज़ा एवं कोटा का बेहतरीन संयोजन है जो भारत के बेहतरीन परिधानों की कलात्मकता के साथ बुना गया है।

गर्मियों से प्रेरित यह कलेक्शन मौसम के बदलते रंगों को सम्मान देता है। सूरज की सुनहरी रोशनी से भीगे पत्तों से लेकर समुंद्र की सतह के नीचे मौजूद कोरल गार्डन्स तक, इस कलेक्शन का पीस अपने आप में विविध होने के बावजूद भी मौसम के रंगों को दर्शाता है। कोमल पेस्टल, हरे-भरे रंग और जीवंत कोरल्स के साथ बेहतरीन प्रिंट एवं हैण्ड पेंट बुनाई की परम्पराओं को समृद्ध बनाते हैं और आपकी वार्डरोब को रोज़ाना के परिधानों से असाधारण परिधानों में बदल देते हैं।

इस कलेक्शन में ब्रीदेबल फैब्रिक से बने रैडी-टू-वियर परिधान और साड़ियां शामिल हैं, जिन्हें भव्यता एवं आधुनिकता के संयोजन के रूप में डिज़ाइन किया गया है। साड़ियों की बात करें तो इसमें राजस्थान के सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, बंगाल के मलमल और जामदानी बुनाई से सजी प्योर कॉटन की साड़ियां शामिल हैं जो रोज़मर्रा के लिए बेहतरीन हैं। इस लॉन्च पर बात करते हुए मिस अनिंदिता सरदार, हैड ऑफ डिज़ाइन, तनाएरा ने कहा, ''गर्मियों का मौसम सहजता, तरलता और जीवंत ऊर्जा का मौसम हैं। हम अपने समर सॉन्स कलेक्शन के साथ ऐसे परिधान और साड़ियां लेकर आए हैं जो इसी सार की अभिव्यक्ति करते हैं। ब्रीदेबल फैब्रिक से बना यह कलेक्शन तय करता है कि आप गर्मी में भी सहज महसूस करें और ये परिधान गर्मियों में आपका साथी बन जाएं। इस तरह के कलेक्शन के साथ तनाएरा ने एथनिक वियर के बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत बना लिया है।'

हार्वर्ड में नहीं पढ़ पाएंगे विदेशी छात्र ! एडमिशन देने पर रोक लगा सकती है ट्रंप सरकार

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप संस्थान माना जाता है, जहां पढ़ने के लिए दुनिया के कोने-कोने से स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। हालांकि, जल्द ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विदेशी छात्रों को एडमिशन नहीं दे पाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हार्वर्ड को चेताया है कि अगर वह सरकारी नियमों को नहीं मानती है तो जल्द ही उसे विदेशी छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो संस्थानों को करोड़ों डॉलर गंवाने पड़ सकते हैं, जो उसे ट्यूशन फीस के तौर पर मिलते हैं। दरअसल, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड ने कहा है कि अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रंप सरकार की मांगों को पूरा नहीं करती है, तो उसे विदेशी छात्रों को एडमिशन देने से रोक दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने बुधवार को यह भी कहा कि हार्वर्ड को मिलने वाले दो डीएचएस ग्रांट, जिनकी कुल कीमत 2.7 मिलियन डॉलर से ज्यादा है, उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। नोएम ने हार्वर्ड से हिंसक गतिविधियों में शामिल विदेशी छात्रों की डिटेल मांगी है।

गलत गतिविधियों में शामिल छात्रों की देनी होगी जानकारी

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले साल फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन हुए, जिसमें विदेशी छात्रों ने भी हिस्सा लिया था। क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अगर हार्वर्ड यह साबित नहीं कर पाता कि वह अपनी रिपोर्टिंग की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों को दाखिला देने का अधिकार खोना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हार्वर्ड को ये बताना पड़ेगा कि उसके विदेशी छात्र किसी तरह की गलत गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। अगर हार्वर्ड ने जानकारी नहीं दी तो उसके एडमिशन देने के अधिकार छिन जाएंगे।

यूनिवर्सिटीज को फंडिंग रोकने की धमकी दे चुकी है सरकार

ट्रंप सरकार ने पहले ही हार्वर्ड समेत कई यूनिवर्सिटीज को मिलने वाली सरकारी फंडिंग में कटौती करने की धमकी दे रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन गाजा पर इजरायल के हमले के बाद शुरू हुए थे। गाजा पर हमला, हमास के चरमपंथियों द्वारा अक्टूबर 2023 में किए गए एक हमले के बाद किया गया था। ट्रंप का कहना है कि ये प्रदर्शनकारी विदेश नीति के लिए खतरा हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारी यहूदी विरोधी हैं और हमास के प्रति सहानुभूति रखते हैं।

जेएनयू प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप, विदेशी शोधकर्ता की शिकायत के बाद बर्खास्तगी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को एक विदेशी शोधकर्ता से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, जेएनयू सूत्रों ने बताया कि, यह कथित घटना कुछ महीने पहले विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने यह पुष्टि की कि यह कोई अकेला मामला नहीं है और प्रोफेसर के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित ने न्यूज़ एजेंसी को बताया यह प्रशासन यौन उत्पीड़कों, किराया मांगने वालों और भ्रष्ट कर्मचारियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के लिए प्रतिबद्ध है।

यौन उत्पीड़न के आरोप में बर्खास्तगी

उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी विश्वविद्यालय के परिसर की सुरक्षा और जवाबदेही पर दृढ़ रुख को दर्शाती है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद - इसकी सर्वोच्च वैधानिक संस्था - द्वारा विस्तृत आंतरिक जांच के बाद लिया गया। पीड़ित, एक जापानी शोधकर्ता, कथित तौर पर विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान संकाय सदस्य द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। जापान लौटने पर, शोधकर्ता ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। यह मामला राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारतीय दूतावास के ध्यान में लाया गया और बाद में विदेश मंत्रालय और विश्वविद्यालय को भेजा गया। आंतरिक शिकायत समिति ने आरोपों को विश्वसनीय पाया। कार्यकारी परिषद ने तब बिना किसी लाभ के बर्खास्तगी की सिफारिश की।

भ्रष्टाचार और अनुशासनात्मक कार्रवाई

इस बीच, पर्यावरण विज्ञान विभाग के एक अन्य संकाय सदस्य को एक शोध परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया। मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है। शोध परियोजना पर तथ्य-खोज समिति की रिपोर्ट के बाद दो गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। अन्य मामलों में, संकाय सदस्यों को वेतन वृद्धि रोकने, निंदा करने और अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण सहित दंड का सामना करना पड़ा है। कार्यकारी परिषद ने आईसीसी में छात्र प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव कराने को भी मंजूरी दे दी है - विश्वविद्यालय के लिए यह पहली बार है- यह सुनिश्चित करते हुए कि छात्र लिंग संवेदनशीलता और सुरक्षा से संबंधित मामलों में प्रत्यक्ष भूमिका निभाएं। जेएनयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा ये निर्णय एक मजबूत संदेश हैं कि विश्वविद्यालय के भीतर ईमानदारी और नैतिकता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

राग और वाद्ययंत्रों पर आधारित होंगी पहली से आठवीं तक की भाषा की किताबें; नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की नई पाठ्य पुस्तकें छात्रों को 21वीं सदी की जरूरतों के आधार पर विषय ज्ञान के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं के अलावा संगीत से भी जोड़ेंगी। पहली से आठवीं कक्षा में भाषा की किताबों के नाम राग और वाद्य यंत्रों पर आधारित हैं। पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत तैयार किया गया है। इसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक विरासत के तत्व भी शामिल हैं। यह लैगिंग समानता, डिजिटल कौशल और पर्यावरण जैसे मूल्यों की शिक्षा देती है। पहली से पांचवीं कक्षा में भाषा की किताबों के नाम भारतीय वाद्य यंत्रों पर आधारित हैं। जबकि छठीं से आठवीं कक्षा तक की भाषा की किताबों के नाम विभिन्न प्रचलित रागों को दर्शाते हैं। इसका मकसद, स्कूली शिक्षा की पढ़ाई के साथ बच्चों को भारतीय परिपेक्ष्य से जोड़ना है।

संविधान की प्रस्तावना पाठ्य पुस्तकों में शामिल

संविधान को कमजोर करने की विपक्ष की आलोचना को खारिज करने की पहल सरकार ने किताबों के माध्यम से की है। आजादी के बाद पहली बार एनसीईआरटी ने अपनी सभी नई पाठ्य पुस्तकों में % संविधान % की प्रस्तावना और उद्देशिका को शामिल किया है। नई पाठ्य पुस्तक खोलते ही छात्र संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे।

पहली व दूसरी कक्षा (फाउंडेशन श्रेणी)

हिंदी– सारंगी (उत्तर भारत का हिंदोस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा प्रसिद्ध वाद्ययंत्र है)

अंग्रेजी– मृदंग (दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र मृदंगम से लिया गया है)

उर्दू– शहनाई (उत्तर भारत का प्रसिद्ध वाद्ययंत्र है, जोकि शुभ मौके पर बजाया जाता है। इसकी पहचान बिस्मिल्लाह खां से होती है)

तीसरी, चौथी व पांचवीं कक्षा(प्रिपरेटरी)

अंग्रेजी- संतुर (कश्मीर का एक लोक वाद्ययंत्र है)

हिंदी-वीणा (दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तंजावुर शहर से जुड़ा वाद्ययंत्र है। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में प्रचलित है। कर्नाटक संगीत में भी मुख्य वाद्य में प्रयोग होता है)

उर्दू- सितार (उत्तर भारत के हिंदोस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है)

छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा (मिडिल स्टेज)

हिंदी- मल्हार (राग मल्हार हिंदोस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रचलित राग है। यह एक बारिश के मौसम से जुड़ा राग है। संगीत सम्राट तानसेन ने इसकी बंदिश बनाई थी)

अंग्रेजी- पूर्वी (शाम ढलने पर गाया जाने वाला हिंदोस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा राग है)

उर्दू- ख्याल (यह भी उत्तर भारत के हिंदोस्तानी राग से लिया गया है)

संस्कृत-दीपकम (तानसेन द्वारा गाया जाने वाले दीपक राग से लिया गया है)

पहली कक्षा से गुड और बैड टच समेत चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में पढ़ेंगे

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिशों के तहत एनसीईआरटी ने पहली कक्षा से सभी पाठ्यपुस्तकों में पॉस्को अधिनियम और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन को भी शामिल किया है। इसका मकसद बच्चों को कक्षा में आने के साथ ही इनके बारे में जागरूक करना है। छात्र इसके बारे में शिक्षक और अभिभावकों से बात करेंगे। इसमें उन्हें अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह की दिक्कत होने पर 24 घंटे में कभी भी छात्र 1098 पर फोन करके मदद मांग सकता है। स्कूलों में आए दिन यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। इसीलिए एनसीपीसीआर ने स्कूलों में छात्रों को इसके बारे में जागरूक करने की मांग रखी थी। लेकिन एनसीआरटी ने इस सभी पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर लिया है।

तीसरी शिक्षा नीति में पहली बार भारतीयता के समिश्रिण को तवज्जो

भारत मे अब तक कुल तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हैं। इसमें पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी 1986 और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। यह पहला मौका है कि जब पाठ्य पुस्तकों में भारतीयता का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। पहली से आठवीं कक्षा तक की भाषा की पाठ्य पुस्तकों में छात्र राष्ट्रीय एकीकरण को समझेंगे। इसमें हर कक्षा में छात्रों को अलग-अलग पाठ्य पुस्तकों में अलग-अलग राज्यों, खानपान, संस्कृति, भाषा,पहनावा, सभ्यता को जानने का मौका मिल रहा है। सर और मैडम की जगह अध्यापक और अध्यापिका होंगे। आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे छात्रों को भारत को समझने का मौका मिलेगा।

चौथी कक्षा में दो लैंग्वेज के साथ मैथ्स, योग और पर्यावरण की पढ़ाई

शैक्षणिक सत्र 2025-26 से चौथी कक्षा में छात्रों को कुल पांच विषयों की पढ़ाई अनिवार्य होगी। दो लैंग्वेज में छात्रों को हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में से कोई दो भाषा पढ़नी जरूरी रहेगी। फिजिकल एजुकेशन या योग और ऑर्ट या पर्यावरण एजुकेशन को नए तरीके से जोड़ा गया है। इसके अलावा मैथ्स भी रहेगा। चौथी कक्षा की नई पाठ्य पुस्तकें बृहस्पतिवार को मार्केट और ई-कॉमर्स साइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। इन सभी पाठ्य पुस्तकों में पहले एक विषय पर पाठ होगा। उसके बाद छात्र ने कितना और क्या सीखा, आदि के लिए एक्टिविटी कॉर्नर होंगे। इससे शिक्षक और अभिभावक बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकेंगे।

शरीर में आयरन बढ़ाने के लिए इन चीजों का सेवन जरूरी

विटामिन, कैल्शियम आदि पोषक तत्व की तरह आयरन शरीर के लिए जरूरी है। इसकी कमी से शरीर में भारी कमजोरी आती है और खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। आयरन बढ़ाने के लिए 6 चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए।

जिस जमीन में नमी, पोषण और ताकत नहीं होती, उसे बंजर कहते हैं। इसी तरह आयरन की कमी शरीर को बंजर बना देती है। यह बॉडी का खून, रेड ब्लड सेल्स और ऑक्सीजन कम कर देती है। आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कुछ उपाय अपनाते रहने चाहिए।

आयरन की कमी से होने वाले रोग

आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं। जिस वजह से एनीमिया यानी खून की कमी का खतरा बढ़ जाता है। यह दिक्कत महिलाओं को सबसे ज्यादा होती है। इसलिए सरकारी स्कूलों में बचपन से ही लड़कियों को आयरन की गोली खिलाई जाती है। शरीर में आयरन बढ़ाने के लिए 6 उपाय हैं। इन 6 खाद्य पदार्थों को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। जो कि आयरन की गोली खाने की नौबत नहीं आने देंगे। आइए पहले आयरन कम होने के लक्षण जानते हैं।

ये लक्षण कर देंगे बुरा हाल

ऑस्ट्रेलिया की सरकारी हेल्थ बेवसाइट के अनुसार आयरन की कमी शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है। जिसकी वजह से निम्नलिखित लक्षण व संकेत दिख सकते हैं।

- हमेशा थकावट रहना
- सांस फूलना
- सिर घूमना
- खून की कमी
- रंग पीला पड़ना
- हाथ-पैर ठंडे होना
- जीभ में सूजन आना
- बार-बार इंफेक्शन होना
- इम्यून सिस्टम की कमजोरी
- बच्चों का विकास रुकना
- भूख ना लगना
- कमजोर नाखून, आदि

आयरन बढ़ाने के उपाय

इन 6 फूड्स को आयरन का भंडार बताया है। इन वेज फूड को डाइट में शामिल करने के बाद आयरन कम होने का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके लिए आप राजगिरा (चौलाई), रागी, किशमिश, दाल, सोयाबीन, करी पत्ता का सेवन बढ़ाएं।

किसमें कितना आयरन?

- 25 ग्राम राजगिरा में 2.8 मिलीग्राम आयरन
- 20 ग्राम रागी में 1.2 मिलीग्राम आयरन
- 10 ग्राम किशमिश में 0.7 मिलीग्राम
- 30 ग्राम दाल में 6.6 मिलीग्राम आयरन
- 30 ग्राम सोयाबीन में 2.4 मिलीग्राम आयरन
- 10 ग्राम करी पत्ता में 0.87 मिलीग्राम

इस वजह से भी कम हो सकता है आयरन

खून बहना, पर्याप्त पोषण ना मिलना आदि कारणों से आयरन डेफिशिएंसी होती है। लेकिन कई बार इसके पीछे आयरन का खराब अवशोषण भी होता है। मतलब आप आयरन देने वाली चीजें खा तो रहे हैं, लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है।

आयरन का इस्तेमाल बढ़ाने के तरीके

- आयरन फूड के साथ विटामिन-सी देने वाले फूड भी खाएं
- खाने के बाद कॉफी और चाय पीने से बचें
- अनाज को खाने से पहले पानी में भिगोएं, अंकुरित और फर्मेंट करें
- लोहे की कढ़ाई या पैन में खाना बनाएं
- लाइसीन अमिनो एसिड और आयरन देने वाला क्विनोआ और फलियां खाएं

इन लक्षणों को पहचानकर ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सकता है

ब्रेन स्ट्रोक में दिमाग की नस फट जाती है। लेकिन इससे काफी पहले छोटा अटैक दिख सकता है। जिसके लक्षणों को पहचानकर ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सकता है।

जब दिमाग की कोई नस ब्लॉक हो जाती है तो ब्रेन स्ट्रोक आता है। यह एक जानलेवा स्थिति है, जिसमें समय पर इलाज ना मिलने पर मौत हो सकती है। लेकिन क्या आप मिनी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानते हैं। जो कि बड़े अटैक से काफी वक्त पहले दिख सकता है। इसके लक्षण हल्के होते हैं, जिन्हें वक्त पर पहचानकर बड़े अटैक से बच सकते हैं। इसे मिनी ब्रेन स्ट्रोक या ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक भी कहते हैं।

दिमाग का छोटा अटैक कब आता है?

ब्रेन स्ट्रोक की तरह छोटा अटैक भी दिमाग की नस ब्लॉक होने से आता है। इसकी वजह से दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। लेकिन ये डैमेज परमानेंट नहीं होती है और 24 घंटे में खुद ही ठीक हो जाती है। मगर इसके लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

पैरालिसिस या स्ट्रोक से कैसे बचें?

- शरीर के एक तरफ पर चेहरे, हाथ या पैर में सुन्नपन या कमजोरी
- अचानक कंफ्यूजन आना
- अचानक बोलने में दिक्कत आना
- अचानक देखने में दिक्कत
- अचानक शारीरिक संतुलन खो जाना
- अचानक चलने में दिक्कत आना
- चक्कर आना
- अकारण तेज और गंभीर सिरदर्द
- निगलने में कठिनाई
- चेहरे की मांसपेशियां गिरना

24 घंटे में गायब हो जाते हैं लक्षण

नसों में ब्लड क्लॉट जमने से मिनी स्ट्रोक पड़ता है। जिससे खून पूरी आजादी के साथ घूम नहीं पाता है। लेकिन ये ब्लड क्लॉट छोटे और अस्थाई होते हैं और कुछ ही देर में वापस घुल जाते हैं। लेकिन इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

मिनी स्ट्रोक से बचने के टिप्स

- धूम्रपान और शराब का सेवन बंद कर दें।
- ताजे फल, सब्जी और साबुत अनाज का सेवन करें।
- शरीर का वजन कंट्रोल रखें।
- नियमित एक्सरसाइज करें।
- फैट का सेवन कम कर दें।
- टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी जैसी बीमारियों की दवा लेते रहें।

स्ट्रोक से बचाने वाली डाइट

- ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए लो फैट, कम नमक के साथ हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। जिसके लिए आप इन फूड्स को खा सकते हैं।
- नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, सेब, केला, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, पालक, टमाटर, दालें, राजमा, छोले, क्विनोआ, ओट्स, बादाम, चिया सीड्स, शकरकंद

कक्षा 1 से 5 तक हिन्दी होगी अनिवार्य, भाषा विरोध के बीच राज्य सरकार का फैसला

मुंबई, एजेंसी।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में इन भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा को भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए अनिवार्य कर दिया है। राज्य में मराठी भाषा को बढ़ाए जाने और हिंदी भाषी लोगों के साथ होने वाली मारपीट की कई घटनाएं सामने आने के बीच राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पाठ्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में यह तीन भाषा फॉर्मूला लाया गया है।

राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस बारे में एक बयान जारी करते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को मानते हुए पाठ्यक्रम को एक नए तरीके से तैयार किया गया है। इस बयान के अनुसार, महाराष्ट्र के अन्य माध्यम स्कूल पहले से ही तीन भाषा फॉर्मूले का पालन कर रहे हैं.. क्योंकि राज्य में मराठी और अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना अनिवार्य है। ऐसे में यह अपने आप ही तीन भाषाएं पढ़ाते हैं। मराठी और अंग्रेजी भाषाओं के स्कूलों में केवल दो भाषाएं पढ़ाई जाती थीं। अब इनमें हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। यह नई नीति अगले शैक्षिणिक वर्ष 2025 से लागू हो जाएगी। इसके अलावा राज्य

सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कई अन्य बदलावों की भी घोषणा की। बयान के मुताबिक नए शैक्षिणिक वर्ष 2025 से अब स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 फॉर्मूले की शुरुआत की जाएगी। इसमें पहले के पांच साल फाउंडेशन स्टेज के होंगे, जबकि कक्षा तीन से 5 तक प्रारंभिक स्टेज के होंगे। कक्षा 6 से आठ मिडिल स्कूल के अंतर्गत आएंगे जबकि अंतिम चार साल माध्यमिक शिक्षा के होंगे।

नई नीति के अनुसार महाराष्ट्र के राज्य बोर्ड की किताबों में भी बदलाव किया जाएगा। यह किताबें भी अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही होंगी। इसके साथ ही इनमें स्थानीय भाषा और भूगोल के हिसाब से सामाजिक विज्ञान में बदलाव किए जाएंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक निदेशक राहुल रेखवार ने कहा कि प्री प्राइमरी सेक्शन के पहले तीन वर्षों के लिए पहले ही पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इसे महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग के सहयोग से लागू किया गया है। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आंगनवाड़ियों में काम करने वाले लोगों के लिए हम कार्यशालाएं आयोजित करेंगे।

झज्जर रोड पर बनेगा बाइपास, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात; अधिकारियों के साथ बनाई रूपरेखा

गुरुग्राम एजेंसी।
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) गुरुग्राम-झज्जर रोड पर जाम को खत्म करने की योजना बना रहा है। इसके तहत धनकोट गांव से बाइपास बनाने की योजना बनाई जा रही है। अगले एक महीने में इस योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ओल्ड गुरुग्राम निवासी गुरुग्राम से झज्जर जाने के लिए बसई रोड का इस्तेमाल करते हैं। धनकोट गांव के पास सड़क संकरी होने से सुबह और शाम में जाम की समस्या बन जाती है। पिछले साल तत्कालीन जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इस सड़क को दुरुस्त करने की योजना बनाई थी।

सेक्टर-102ए स्थित एमआर गुड़गांव ग्रींस सोसाइटी के पास से वैकल्पिक रास्ता निकाला था, जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर आकर मिलता था, लेकिन गुरुग्राम नहर के पास सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की योजना पर काम नहीं हुआ था। ऐसे में इस सड़क पर रोजाना जाम लगता है। इससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। सुबह और शाम में आधा किलोमीटर लंबे इस हिस्से को पार करने में 20 से 25 मिनट लग जाता है। इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर शहरी विकास के प्रधान सलाहकार सेवानिवृत्त मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने तैयारी शुरू की है।

पिछले सप्ताह इस सिलसिले में जीएमडीए अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। इसमें मुख्य अभियंता अरुण धनखड़, वरिष्ठ नगर योजनाकार नरेश कुमार, सलाहकार एसके चहल, कार्यकारी अभियंता विकास मलिक आदि मौजूद थे। बैठक में गुरुग्राम-मानेसर विकास योजना को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान देखा गया कि सेक्टर-99-99ए को विभाजित कर रही मुख्य सड़क आगे जाकर गुरुग्राम-झज्जर रोड से जुड़ रही है, लेकिन करीब 500 मीटर

लंबी सड़क को लेकर जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। ऐसे में विचार हुआ कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की मदद से प्रस्तावित सड़क के इस हिस्से के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाए। सेक्टर-99-99ए की मुख्य सड़क के निर्माण में जहां-जहां विवाद है, उन्हें दूर किया जाए।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्य भर में वृद्धाश्रम निर्माण की धीमी गति पर गंभीर चिंता जताई है। वर्तमान में रेवाड़ी जिले में केवल एक वृद्धाश्रम चल रहा है और वह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकार द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक और सिरसा में वृद्धाश्रमों के लिए भूमि की पहचान नहीं की गई है। इस बीच, गुरुग्राम, कैथल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नूंह जैसे जिलों ने भूमि चिह्नित कर निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी है। फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुनानगर में नियोजन अनुमोदन की कमी के कारण निर्माण लंबित है। हालांकि, करनाल (स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत) और पंचकूला (माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की देखरेख में) में काम चल रहा है।

फरीदाबाद में मोबाइल मांग रहा था छात्र, नहीं मिलने पर सुसाइड

फरीदाबाद एजेंसी।
फरीदाबाद में मोबाइल नहीं मिलने से परेशान नौंवी कक्षा के एक छात्र ने मंगलवार शाम अपने घर में फंदा लगाकार खुदखुशी कर ली। उसकी पहचान सूर्या विहार पार्ट दो निवासी 15 वर्षीय नितिन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नितिन तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। वह दिल्ली के मीठापुर स्थित राजकीय स्कूल में नौंवी कक्षा में पढ़ता था। वह अपने माता-पिता के साथ पल्ला के सूर्या विहार पार्ट दो स्थित 30 गज में बने एक मकान में रहता था। उसके पिता एक कंपनी में काम करते हैं। अक्सर वह मोबाइल फोन देखता रहता था। इससे उसके माता-पिता परेशान थे। वह कई बार इस बाबत टोका और डांटा भी जाता था। बेटे का मोबाइल फोन चलाने का लत दूर हो, इस बाबत उसके माता-पिता मोबाइल को रिचार्ज भी नहीं कराते थे। मंगलवार शाम उसकी मां घर में काम कर रही थी। साथ ही पिता ड्यूटी पर थे। काम से फुर्सत पाकर जब उसकी मां उसके कमरे में गई तो देखा कि नितिन कसरत करने के लिए बनाए पुलअप बिंब में बंधे गमछे के फंदे से लटका था। यह देखकर उसकी मां के होश उड़ गए और चीखें निकल गईं। उन्होंने तुरंत मोबाइल फोन पर कॉल करके पति को जानकारी दी। फिर डायल-112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे तुरंत बीके अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पल्ला थाना के एसएचओ रणवीर सिंह ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वह पुलअप के लिए बांधे बिंब से लटका था। पुलिस आत्महत्या करने के कारणों की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार नितिन व्यायाम करने का शौकीन था। वह रोजाना एक घंटे से अधिक समय तक कसरत करता था। वह खेलने के आसपास के मैदान में जाने के बाद भी वहां पुसअप आदि करता था। वह अक्सर सोशल मीडिया पर कसरत करने के तरीकों की वीडियो आदि भी देखता था। यहां तक कि इस तरह का वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। बताया जा रहा है कि वह भारतीय सेना या पुलिस में नौकरी करने की ईच्छा रखता था। ऐसे में सेना या पुलिस में भर्ती होने के लिए शरीर को जरूरी लंबाई तक पहुंचाने की कोशिश करता था। वह अक्सर पुलअप करता था।

ग्रेटर नोएडा में पेड़ से टकराई स्कूल बस, मच गई चीख-पुकार

ग्रेटर नोएडा एजेंसी। ग्रेटर नोएडा में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। गाजियाबाद के एक स्कूल की बस गुरुवार की सुबह थाना बिसरख क्षेत्र के चार मूर्ति चौराहे पर अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, जिससे बस में सवार चार बच्चे घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और बस में सवार बच्चों को दूसरी बस से स्कूल भेजा। कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं।

इस बीच, बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर पाकर घबराए हुए अभिभावक मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्कूल प्रशासन और बस संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आज सुबह थाना बिसरख क्षेत्र के चार मूर्ति चौराहे पर एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर पेट से टकराने सूचना मिली। उन्होंने बताया कि यह बस गाजियाबाद के प्रताप विहार स्थित ब्लूम पब्लिक स्कूल की है।

एनसीआर में गरजा बुलडोजर, फरीदाबाद में दुकानें तोड़ीं; नोएडा में 150 करोड़ की जमीन कराई खाली

नोएडा एजेंसी।
एनसीआर क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। फरीदाबाद में दुकानों को तोड़ा गया। वहीं नोएडा में 150 करोड़ से ज्यादा की जमीन खाली कराई गई, जिसपर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थीं। ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-87 में बुधवार को मास्टर रोड किनारे बनी अवैध दुकानों पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने तोड़फोड़ की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानों को गिराया गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के दौरान एक युवक अपनी दुकान की छत पर चढ़ गया और अन्य लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में हंगामा नहीं बढ़ सका। अधिकारियों का कहना है कि शहर का विकास मास्टर प्लान के अनुसार ही किया जाएगा और अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एसडीओ राजपाल ने बताया कि दो दिन पहले ही सभी दुकानदारों को

दुकानें खाली करने के लिए कहा गया था और अवैध निर्माण की निशानदेही भी कर दी गई थी। नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को हैबतपुर गांव स्थित डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। 120 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है। यहां अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं। हैबतपुर में अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर नोएडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन की टीम ने अभियान चलाया और यहां बनी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया। अभियान में 250 से अधिक कर्मचारियों, तीन जेसीबी और पांच डंपर लगे थे। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने कहा कि इस इलाके में अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे डूब क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त न करें। यहां पर पक्का निर्माण नहीं हो सकता और न ही किसी प्रकार की सुविधाएं यहां पर लोगों को मिलेंगी।

शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की वार्षिक कार्यकारिणी की बैठक आयोजित

संभागायुक्त श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में आज संभागायुक्त कार्यालय में शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर की वार्षिक कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के नियमित आय-व्यय के साथ रोगियों की सुविधा बढ़ाने हेतु नवीन उपकरण यंत्रों की खरीदी, संस्थान के नवीन शैक्षणिक भवन एवं पुस्तकालय के डिजीटलाइजेशन आदि बिन्दुओं पर प्रगति रिपोर्ट देखी और उसकी समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र रघुवंशी, राऊ एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा, संस्थान के प्राचार्य डॉ. एपीएस चौहान, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉ. एस.पी. सिंह, संभागीय आयुष अधिकारी डॉ. हंसा बारिया, नई दिल्ली के प्रतिनिधि डॉ. सुश्रुत कनोजिया, लोक निर्माण विभाग के श्री अभय दुबे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में इलाज/जांच के लिए आने वाले रोगियों के साथ संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान की जाये। आयुष चिकित्सक मरीजों के साथ मधुर संबंध बनाये।

बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि नवीन उपकरण एवं यंत्रों की खरीदी में पारदर्शिता, ईमानदारी एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। संस्थान के उत्तरोत्तर प्रगति हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाये। मरीजों के आराम करने के लिए विशेष बैठक व्यवस्था के साथ-साथ बुनियादी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाये। बैठक में शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एनएबीएस एक्रीडेशन जैसे गुणवत्तापूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई।